जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 117 प्रभात चूरू, रविवार 24 अगस्त, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

यूरोपीय देश एकजुट होकर अमेरिका के साथ खड़े हुए यूक्रेन के मुद्दे पर

पुतिन कुण्ठित हुए, अकेले पड़ने से, तथा उन्होंने यूरोपीय देशों पर कटाक्ष किया कि इन देशों ने अपनी ''सॉवरैनिटी'' (संप्रभुता) गिरवी रख दी है

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन,23 अगस्त। ऐसे में जबकि पश्चिमी देश अमेरिका के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन ने उन सभी पर तीखा हमला बोल है।

कुछ हद तक अलग-थलग पड़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब उन पश्चिमी सहयोगियों पर सीधा हमला बोला है जिन्हें अब कोएलिशन ऑफ द विलिंग (इच्छुकों का गठबंधन) कहा जा रहा है। पहले जहाँ यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच साफ-साफ मतभेद था, अब समीकरण बिल्कुल उलट गए है। पूरा पश्चिमी ब्लॉक अमेरिका के साथ आ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व को खुले तौर पर मान्यता दे रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह तस्वीर है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रंप बीच में बैठे हैं और उनके चारों ओर पश्चिमी यूरोप के नेता ऐसे बैठे हैं जैसे किसी कक्षा में बच्चों को शिक्षक समझा रहे हों।

इस नए गठबंधन पर स्पष्ट टिप्पणी करते हुए, रूसी राष्ट्रपति ने अपने घरेलू दर्शकों को संबोधित भाषण में,जो कि साफ तौर पर उनके अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के लिए था, कहा कि ''पश्चिमी यूरोप के देशों ने स्पष्ट रूप से अपनी संप्रभुता खो दी है।''

- पुतिन ने कहा कि रूस कभी भी अपनी संप्रभुता गिरवी रखकर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने चीन, भारत व बांग्लादेश के साथ मिलकर अपना अलग गुट बनाने की बात कही।
- पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की अन्य देशों से दोस्ती व सम्बन्ध बनाने का आधार होता है, उन देशों से सहयोग करके, उन देशों के साथ उन देशों के विकास में भागीदार होना, जबकि अन्य देश (अमेरिका) अन्य देशों को केवल एक मार्केट के रूप में देखता है। जैसा कि विदित ही है, रूस बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लॉन्ट बना रहा है।
- साथ ही रूस ने अमेरिका के साये में यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता व मुलाकात का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। हालांकि, रूस ने औपचारिक तौर पर कहा यही है, कि यूक्रेन अभी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी भूमि छोड़ने व नाटो की सदस्यता को छोड़ने का इरादा त्यागने पर अभी तक सहमति नहीं दी है।

अपना स्टेटस गंवाने की इन देशों की स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए पुतिन ने कहा कि कई देश अपनी संप्रभुता खोने के बाद भी अपने स्टेटस से संतुष्ट हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि रूस इस रास्ते पर नहीं चलेगा और कभी भी इन बुनियादी सिद्धांतों पर समझौता नहीं करेगा।

पुतिन ने यह भी कहा कि भले ही पश्चिमी गोलार्ध में रूस अकेला पड़ गया हो, लेकिन वह अपने खुद के देशों का गठबंधन बना रहा है। उन्होंने साफ तौर पर चीन, भारत और बांग्लादेश का उल्लेख किया। चीन के साथ रूस की ''अनंत मित्रता'' की बात करते हुए उन्होंने भारत और बांग्लादेश के साथ सहयोग के विशेष क्षेत्रों को रेखांकित किया। ज्ञातव्य हैं कि रूस बांग्लादेश में कुछ परमाणु बिजलीघर भी बना रहा है।

उन्होंने रूसी दृष्टिकोण की ओर इशारा किया जिसमें रिश्ते, सहयोग और स्थानीय विकास के स्तर पर बनाए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश केवल अपने उत्पाद बेचने में लगे रहते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खराब लड्डू बेचे, हलवाई पर जुर्माना

जयपुर, 23 अगस्त। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने ग्राहक को सवामणी प्रसादी के लिए खराब लड्डू बेचने पर कंवर नगर निवासी हलवाई संजय कुमार शर्मा पर 11 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं हलवाई को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक को खराब लड्डुओं की कीमत 18,500 रुपए भी ब्याज सहित वापस करे। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश मानसरोवर निवासी राकेश गर्ग के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसके द्वारा दूषित लड्डू नहीं बेचे गए थे। ऐसे में यह विपक्षी की ओर से सेवाओं में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस है। ऐसे में विपक्षी पर हर्जाना लगाया जाना उचित होगा।

- जिला उपभोक्ता आयोग ने सवामणी के लिए खराब लड्डू बेचने पर ब्याज सहित कीमत लौटाने तथा 11 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार, परिवादी ने खोले के हनुमानजी मंदिर में सवामणी प्रसादी के लिए 22 फरवरी 2022 को 50 किलो चौगानी लड्डू 18,500 रुपए में खरीदे थे। उसने लड्डू का मंदिर में भोग लगाकर परिजनों को प्रसादी वितरण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एन.डी.ए. के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं अमित शाह के विधेयक को पास कराने के लिए

इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत, यानि 365 सदस्यों का समर्थन चाहिये, जबकि एनडीए के पास 293 सांसद हैं, लोकसभा में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ला ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 अगस्त। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में एक विवादित बिल पेश किया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। लेकिन यह बिल आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है।

हालांकि, बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है, मगर इसे पास करने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई यानि 365 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि एनडीए के पास सिर्फ 293 सांसद हैं। जो इस संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

बिल बिना किसी सलाह-मशविरे के लाया गया था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू इसका समर्थन नहीं करें, जिससे एनडीए की ताकत और घट जाएगी।

असल में, इस बिल के जरिए इन दो सहयोगी दलों को डराने की कोशिश की गई थी कि वे एनडीए का साथ देते रहें नहीं तो उनके मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों (जैसे ईडी या सीबीआई) के शिकंजे में फंस जाएंगे और क्योंकि, वो 100 दिन जेल में रहेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि अदालतें सामान्यतः 100 दिनों में जमानत नहीं देतीं। संविधान विशेषज्ञ पी.डी.टी. आचार्य 14वीं और 15वीं लोकसभा के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमित शाह के विधेयक के अनुसार, प्र.मंत्री, मु.मंत्री या अन्य कोई मंत्री की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी,अगर वह, 100 दिन से अधिक जेल में कैद रहेगा।
- इस विधेयक को लाने से पहले एनडीए के अन्य घटकों को विशेषकर, चन्द्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार को विश्वास में नहीं लिया गया था, अतः सम्भावना है, कि तेलगुदेशम व जद (यू) भी इस विधेयक के पक्ष में वोट नहीं करेंगे।
- ये दिक्कतें आयेंगी, यह जानते हुए भी, यह विधेयक लोकसभा में क्यों पेश किया गया, यह एक विचारणीय प्रश्न है।
- विपक्ष का प्रचार है, कि प्रायः न्यायालय सौ दिन में जमानत नहीं दे पाते हैं, अतः यह विधेयक उन मुख्यमंत्रियों को चेतावनी देने के लिए लाया गया है, जो सरकार को उत्साहजनक समर्थन नहीं दे रहे हैं, अतः उन पर सदस्यता रद्द करने के लिए ई.डी., सी.बी.आई. की ''रेड'' करवाई जा सकती है।

'अमेरिका के लिए सौ डॉलर से ज्यादा कीमत की डाक सेवाएं बंद'

भारतीय डाक विभाग का यह आदेश 25 अगस्त से क्रियान्वित होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 अगस्त। भारतीय डाक विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए 100 डॉलर से अधिक मूल्य वाली अधिकांश अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएँगी। यह कदम अमेरिकी सरकार के नए नियमों के बाद उठाया गया है।

अमेरिका ने 30 जुलाई 2025 को जारी आदेश (एक्ज़िक्यूटिव ऑर्डर न. 14324) में 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट खत्म कर दी है। अब 29 अगस्त से अमेरिका आने वाले हर सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। केवल 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम ड्यूटी-फ्री रहेंगे।

- अमेरिका ने 30 जुलाई 2025 को जारी आदेश में 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट खत्म कर दी है, अब अमेरिका भेजे जाने वाले हर सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। सिर्फ 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम ही ड्यूटी फ्री रहेगें।

नए आदेश के तहत अब केवल वे ट्रांसपोर्ट कैरियर्स या क्वालिफाइड पार्टियां जिन्हें अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन (सी.बी.पी.) मान्यता देगा, वे ही ड्यूटी वसूल कर सरकार को जमा कर पाएँगे। हालांकि, इन प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

इसी वजह से अमेरिका जाने वाली एयरलाइनों ने कहा है कि वे 25 अगस्त के बाद ऐसे डाक पार्सल स्वीकार नहीं कर पाएँगी।

डाक विभाग ने बताया कि अब अमेरिका के लिए सिर्फ पत्र, दस्तावेज और 100 डॉलर तक के गिफ्ट पैकेट ही भेजे जा सकेंगे। अन्य सभी प्रकार की डाक सेवाएँ अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी।

जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसे पार्सल बुक कर दिए हैं जिन्हें अब भेजा नहीं जा सकता, वे डाक शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डाक विभाग का कहना है कि वह सी.बी.पी. और अमेरिका की डाक सेवा से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द ही सभी सेवाएँ फिर से शुरू की जा सकें।

सीबीआई ने अनिल अंबानी के दो परिसरों की तलाशी ली

नयी दिल्ली, 23 अगस्त। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2929.05 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी अनिल अंबानी के मुंबई स्थित दो ठिकानों पर शनिवार को तलाशी ली।

सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर की है, जिसने 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था। यह कार्रवाई आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार की गई थी।

- बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई की विशेष अदालत से तलाशी वारन्ट लिया था।

सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष अदालत से तलाशी वारंट हासिल किया था।

अपने सबसे विश्वास पात्र सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया ट्रंप ने

गोर सिर्फ भारत में राजदूत का काम नहीं देखेगें बल्कि उन्हें समूचे दक्षिणी और मध्य एशिया मामलों का विशेष राजदूत भी बनाया गया है

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 23 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने के लिए चुना है। गोर लम्बे समय से ट्रंप के सहयोगी हैं और वर्तमान में वाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह घोषणा जारी, और कहा वह जिसमें उन्होंने गोर को एक ''विश्वसनीय सहयोगी'' बताया जो कई वर्षों से मेरे साथ रहे हैं।

ट्रंप ने कहा कि 38 वर्षीय गोर को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में भी काम करेंगे, जिससे उनके अधिकार राजदूत पद से आगे, एक व्यापक क्षेत्रीय स्तर तक बढ़ जाएंगे। यह नामांकन ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापार और शुल्क को लेकर तनाव जारी है।

अपनी घोषणा में ट्रंप ने गोर की प्रशासन में भूमिका की प्रशंसा की और उन्हें संघीय विभागों और एजेंसियों में लगभग 4,000 अधिकारियों की नियुक्ति को ''रिकॉर्ड समय'' में संपन्न कराने का श्रेय दिया। राष्ट्रपति के अनुसार, अब इन पदों में से 95 प्रतिशत से अधिक भरे जा चुके हैं। सीनेट द्वारा नियुक्ति पुष्टि होने तक गोर अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे।

- ट्रंप ने कहा, यह जरूरी है कि विश्व के इस सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को लाऊं जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं, कि वह मेरा ऐजेंडा लागू कर सकता है। कहा जा रहा है कि इससे ट्रंप भारत पर पूरी नज़र रख सकेगें।
- गोर की नियुक्ति की अभी सीनेट से पुष्टि होना बाकी है। वे भारत में एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे जो मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में राजदूत थे।
- जहां तक भारत की बात है, यहाँ हमेशा ऐसे अमेरिकन राजदूत को ज्यादा स्वीकृति दी गई है जो राष्ट्रपति का बेहद करीबी रहा हो, ऐसे में संदेश सीधे राष्ट्रपति तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।

ट्रंप ने आगे कहा, ''दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं, जो मेरे एजेंडा को आगे बढ़ाए और अमेरिका को फिर से महान बनाए। सर्जियो एक शानदार राजदूत बनेंगे। बधाई हो, सर्जियो!''

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी इस चयन का समर्थन किया और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोर हमारे देश के लिए भारत में एक शानदार राजदूत साबित होंगे।

यदि सीनेट द्वारा पुष्टि हो जाती है, तो गोर एरिक गार्सेटी का स्थान लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था। यह पद कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यह भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका के बढ़ते महत्व को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका, अखिलेश, स्टालिन राहुल की यात्रा में शामिल होंगे

नयी दिल्ली 23 अगस्त। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव, एम के स्टालिन तथा हेमंत सोरेन जैसे प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां बताया कि गांधी की यात्रा में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन,

- कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी बताया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यात्रा में शामिल होंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तथा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि गांधी की 17 अगस्त को बिहार के सासाराम में शुरु हुई वोटर अधिकार यात्रा 20 जिलों को कवर करते हुए 1300 किमी चलने के बाद एक सितंबर को पटना में समाप्त होगी।

इलैक्ट्रॉनिक फार्मास्युटिकल व सोलर एनर्जी के सामान व स्पेयर पार्ट्स के लिए भारत चीन पर काफी निर्भर है

दूसरी ओर 2020 में गलवान घाटी पर संघर्ष के बाद, भारत में चीन को संशय की दृष्टि से देखा जाता है

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 23 अगस्त। भारत की विदेश नीति अब एक विरोधाभास से परिभाषित होती जा रही है। एक ओर, इसकी राजनीतिक और सुरक्षा रणनीति इसे अमेरिका के करीब धकेलती है। तो दूसरी ओर, इसकी आर्थिक मजबूरियाँ और बहुपक्षीय मंचों पर इसकी स्थिति अक्सर इसे चीन के साथ सामरिक मेलजोल में ला देती हैं। यह दोहरी रणनीति कोई भ्रम नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता की भारत की सोच-समझकर अपनाई गई नीति है। लेकिन इससे वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ तनाव भी उत्पन्न होता है, जिससे दिल्ली को एक नाज़ुक संतुलन बनाए रखना पड़ता है।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी का राजनीतिक और रणनीतिक तर्क सीधा है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घातक झड़प के बाद से भारत ने चीन को अपने दीर्घकालिक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना शुरू किया। दोनों देश अब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा तनाव में उलझे हुए हैं, जहाँ सैनिक जमावड़े और आमने-सामने की स्थितियाँ बनी हुई हैं। भारत में जनमत और राजनीतिक दृष्टिकोण चीन के खिलाफ काफी सख्त हो गया है, और चीन को भारत की संप्रभुता के लिए मुख्य खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

इस खतरे का संतुलन साधने के लिए दिल्ली ने अमेरिका के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग तेज कर दिया है। क्वाड समूह-अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत-इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। मालाबार जैसे नौसेना अभ्यास, खुफिया साझेदारी समझौते और तकनीकी हस्तांतरण सौदे भारत को एशिया में अमेरिका के सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करते हैं।

राजनीतिक रूप से, दोनों देश अपनी साझेदारी को लोकतंत्रों के मेल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, भले ही दिल्ली घरेलू शासन पर उपदेश को अस्वीकार करता है। वहीं, अमेरिका भारत को अब चीन के साथ अपनी व्यापक प्रतिस्पर्धा में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में देखने लगा है।

- पर, अमेरिका की टैरिफ नीति में भारत विरोधी रूझान, भारत को चीन के नज़दीक धकेलता है।
- अतः भारत व चीन का रिश्ता, आपसी विश्वास पर आधारित नहीं, बल्कि आपसी राजनीतिक आवश्यकता के कारण पनपने को मजबूर है।
- इसी प्रकार भारत चीन द्वारा सीमा पर अपनाये गये आक्रामक रवैये से चौकन्ना होकर, अमेरिका के नज़दीक जाने की सोचने लगता है, क्वाड की संघीय सदस्यता (यू.एस., जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत को मैत्री ग्रुप की मैम्बरशिप), नौसैनिक अभ्यास, इन्टैलिजेन्स शेयरिंग के समझौते व टैक्नॉलोजी ट्रांसफर के अनुबन्धन, इसी प्रयास के नमूने हैं।
- इन दो विरोधाभासी दबावों के बीच भारत का अपनी कूटनीतिक नाव खेना, काफी नाज़ुक संतुलन का काम है।

फिर भी, जहाँ राजनीति भारत को पश्चिम की ओर ले जाती है, वहीं अर्थव्यवस्था चीन के साथ मेल के लिए मजबूर करती है।

चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्त्रोत है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों से लेकर सौर ऊर्जा तक के उद्योगों के लिए आवश्यक घटक प्रदान करता है। भले ही भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासरत है, लेकिन वह फिलहाल और निकट भविष्य में चीनी घटकों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। बहुपक्षीय स्तर पर, भारत अक्सर ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में चीन के रुख के पक्ष में होता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी के खिलाफ टिप्पणी, तेजस्वी पर मुकदमा

ललितपुर 23 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिलाध्यक्ष हरिश्चन्द्र रावत ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई है।

- बिहार से भाजपा जिला अध्यक्ष ने यह मुकदमा दर्ज किया जिसमें आरोप है कि तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है।

कोतवाली तालबेहट अंतर्गत मुहल्ला सरफयाना निवासी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने कोतवाली तालबेहट में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि पीएम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK CMYK